

वर्ष 12 • अंक 18 • 14 पृष्ठ

• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 8 मार्च 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

एक नज़र

फोक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपये जुर्माना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फोक्सवैगन पर डीजल कारों में उत्सर्जन का स्तर छिपाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा है। कंपनी ने कहा कि वह एनजीटी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।

पृष्ठ 2

सरकार पहली बार जारी करेगी 20 रुपये का सिक्का

सरकार पहली बार 20 रुपये का सिक्का जारी करेगी। यह सिक्का 12 कोणीय होगा, जिस पर अनाज के निशान होंगे। ये निशान देश में कृषि क्षेत्र की प्रधानता को इंगित करेंगे। इसके अलावा नई श्रृंखला के 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए जाएंगे। ये सिक्के गोलाकर होंगे और सिक्के की राशि हिंदी में लिखी होगी। इन सिक्कों को जारी करने की तारीख की फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा कि 20 रुपये का सिक्का 8.54 ग्राम का होगा और इसका बाहरी व्यास 27 मिली मीटर होगा।

जम्मू में ग्रेनेड हमले में 1 की मौत, 32 घायल

जम्मू शहर भीड़-भाड़ वाले एक बस स्टैंड इलाके में गुरुवार को संदिग्ध आतंिकियों द्वारा किए गए धमाके में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हो गए। पिछले साल मई से लेकर अब तक बस स्टैंड इलाके में आतंकवादियों द्वारा हथगोले से किया गया यह तीसरा हमला है। पुलिस का कहना है कि ग्रेनेड हमला करने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जेट एयरवेज के 119 विमानों में मात्र 70 सेवा में

निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के बेड़े में शामिल कुल 119 विमानों में फिलहाल केवल 70 ही परिचालन में हैं। नागर विमानन महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कंपनी के बाकी 49 विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं। अधिकारी ने संकेत दिया कि स्थिति नाजुक है और कंपनी के कुछ और विमान जमीन पर आ सकते हैं। जेट एयरवेज गंभीर नकदी संकट से गुजर रही है।

आज का सवाल		
क्या नई नीति से बिजली क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा		
www.bshindi.com पर राय भेजें। आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो BSP Y और यदि न है तो BSP N लिखकर 57007 पर भेजें।		
पिछले सवाल का नतीजा		
क्या नए मानक पर बैंकों को मिलेगी आरबीआई से मोहलत?	हां नहीं	54.55% 45.45%

बिज़नेस स्टैंडर्ड सालाना इंश्योरेंस राउंड टेबल

बीमा किस्त पर कर लगाना घातक: साठे

बीएस संवाददाता
मुंबई, 7 मार्च

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के सदस्य निलेश साठे का कहना है कि बीमा किस्त पर 18 फीसदी कर वसूलना देश में बीमा के प्रसार में बाधक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। साठे ने बुधवार को बिज़नेस स्टैंडर्ड के सालाना इंश्योरेंस राउंड टेबल में बतौर मुख्य अतिथि अपने मुख्य भाषण में कहा, ‘देश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बेहद सीमित है और ऐसे में किस्त पर 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाना घातक है। क्या आपको लगता है कि देश में बीमा का दायरा बढ़ाना केवल आईआरडीएआई या बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है ? यह हर संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी है जिसमें सरकार भी शामिल है।’ उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने सरकार को बताया है कि अधिकांश देशों में बीमे की किस्त पर कोई कर नहीं लिया जाता है। इन देशों में विकसित बाजार भी शामिल हैं।

साठे ने कहा कि सरकार को बीमा कंपनियों के पेंशन उत्पादों के लिए अलग श्रेणी की अनुमति देनी चाहिए। यह नई पेंशन योजना (एनपीएस) की तर्ज पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘बीमा कंपनियां पहले से ही पेंशन के क्षेत्र में भी सक्रिय

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अरवबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com



►► पृष्ठ 6

एमसीएक्स का कपास वायदा रिकॉर्ड स्तर पर

तुलसी तांती ►► पृष्ठ 2

विदेशी ऋण का पुनर्गठन करेगी सुजलॉन



डॉलर ₹. 70. 00 ▼ 30 पैसे | यूरो ₹. 79. 20 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) ₹. 31975 ▼ 120 रुपये | सेंसेक्स 36725. 40 ▲ 89. 30 | निफ्टी 11058. 20 ▲ 05. 20 | निफ्टी प्सूवसं 11098. 20 ▲ 40. 00 | बैंट कूड 66.30 डॉलर ▲ 01.00 डॉलर

बिजली क्षेत्र में निवेश के उपाय

नई बिजली परियोजनाओं, सुधार योजना और पनबिजली नीति को मिली मंजूरी

श्रेया जय
नई दिल्ली, 7 मार्च

संकटग्रस्त बिजली क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कुल 31,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं को आज मंजूरी दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में दो ताप बिजली और दो पनबिजली परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही पनबिजली नीति एवं अटकी परियोजनाओं के पुनरुद्धार योजना को भी हरी झंडी दे दी।

पिछले एक दशक से पनबिजली क्षेत्र में निवेश का टोटा है, ऐसे में लंबे समय में लंबित नीतिगत उपायों को मंजूरी मिलने से इस क्षेत्र में सुधार की संभावना देखी जा सकती है। 25 मेगावाॉट से अधिक की क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाएं अब अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में आएंगी। इससे राज्यों को पनबिजली खरीदने के बाध्यता होगी और उसे प्राथमिकता मिलेगी। इससे भारत कार्बन उत्सर्जन के आईएनडीसी के अपने एक लक्ष्य – कुल ऊर्जा खपत का 40 फीसदी आपूर्ति अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने में सक्षम हो सकेगा।

केंद्रीय बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि लागत



कम रखने के लिए पनबिजली इकाइयों के सहायक बुनियादी ढांचे के लिए बजट सहायता मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा, ‘बाढ़ आधुनिकीकरण कंपोनेंट की लागत, सड़क तथा पुलों आदि के लिए बजट सहायता दी जा सकती है। यह 200 मेगावाॉट की परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाॉट 1.5 करोड़ रुपये तक और 200 मेगावाॉट परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाॉट 1 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।’

इन्हें मंजूरी

■ 10,439.09 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,320 मेगावाॉट की बक्सर सुपर ताप बिजली परियोजना

■ 11,089.42 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,320 मेगावाॉट की खूर्जा सुपर ताप बिजली परियोजना

■ 4,287.59 करोड़ रुपये की लागत वाली किरु पनबिजली परियोजना

■ तीस्ता पनबिजली परियोजना के छठे चरण को मंजूरी

सिंह ने कहा, ‘हमने सभी बैंकों के साथ चर्चा की और उन्होंने कर्ज पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई। हम परिचालन के शुरुआती वर्षों में पनबिजली परियोजनाओं की लागत कम करना चाहते हैं।’

मंत्रिमंडल ने पनबिजली इकाइयों में निवेश के दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। 624 मेगावाॉट की किरू पनबिजली परियोजना की 4,287.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स कर रही है। यह एनएचपीसी, जम्मू कश्मीर राज्य बिजली विकास निगम तथा पीटीसी इंडिया का संयुक्त उपक्रम है। सिक्कम में तीस्ता के छठे चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर द्वारा विकसित की जा रही है। वित्तीय संकट के कारण परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट में परियोजना के खिलाफ ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए एनएचपीसी ने 907 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली में परियोजना का जीवनकाल बढ़ाकर 40 साल किया गया है, वहीं कर्ज पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। नीति में हर साल 2 फीसदी शुल्क बढ़ाने की अनुमति भी दी गई है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

अब जल्द निपटेंगे वैट मामले

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मार्च

दिल्ली सरकार वैट के पुराने मामले जल्द निपटाना चाहती है। इसके लिए वैट विभाग ने छोटे अधिकारियों को छोटे मूल्य के विवादित वैट मामले निपटाने का अधिकार देने के साथ ही प्रत्येक जोन/वार्ड के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है।

इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली की करीब 1,650 अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो इन अनधिकृत बस्तियों के निवासियों को जमीन का मालिकाना हक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की सिफारिशें करेगी। यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।

दिल्ली वैट विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहले जुमाने, ब्याज व आकलन संबंधी विवादित वैट मामलों के निपटारे का अधिकार विशेष/अतिरिक्त /संयुक्त आयुक्त जैसे आला अधिकारियों के पास था। इन

■ छोटे वैट मामले निपटाने के लिए जोन के हिसाब से अधिकारियों की दी गई जिम्मेदारी

■ **5 लाख रुपये तक के मामलों को कनिष्ठ अधिकारी देखेंगे**

वर्ष 2015–16 की अवधि के 5 लाख रुपये मूल्य तक के विवादित मामलों को निपटाने के लिए अब जोन/वार्ड के हिसाब से अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये अधिकारी उक्त अवधि के ऐसे मामलों को ही निपटाएंगे जो विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्तों ने भेजे हैं। दिल्ली बिक्री कर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि वैट विभाग के पास 10 साल पुराने वैट करीब 40 हजार मामले लंबित हैं। इन मामलों के निपटारे के लिए छोटे अधिकारियों को अधिकार देना और वार्ड के हिसाब से अधिकारियों को नियुक्ति अच्छा कदम है।

राइट इश्यू में भारती के प्रवर्तक भी लेंगे हिस्सा

मेघा मनचंदा

नई दिल्ली, 7 मार्च

दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने आज कहा कि जीआईसी प्रा. लि. (पूर्व नाम गवर्नमेंट ऑफ सिंगापर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन) ने कंपनी के 25,000 करोड़ रुपये के राइट इश्यू को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी को इससे अपना कर्ज कम करने तथा बहीखाते को दुरुस्त करने में मदद मिल सकती है। भारती एयरटेल का प्रवर्तक भारती समूह तथा सिंगटेल 11,785.7 करोड़ रुपये का राइट निर्गम खरीदेगी, वहीं जीआईसी 5,000 करोड़ रुपये के राइट इश्यू खरीदेगी।

जीआईसी सिंगापुर सरकार का सॉवरिन वेल्थ फंड है, जिसकी स्थापना 1981 में सिंगापुर के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। विश्लेषकों का मानना है कि निर्गम की पूरी बिक्री नहीं होने या 90 फीसदी से कम बिक्री होने की स्थिति से बचने के लिए भारती एयरटेल का यह सकारात्मक कदम है। ऐसी स्थिति में बाह्य निवेशक और प्रवर्तक इस निर्गम में निवेश कर सकते हैं।

भारती एयरटेल में प्रवर्तकों की 67 फीसदी हिस्सेदारी है और राइट निर्गम शेयरधारिता के अनुरूप हैं। भारती एयरटेल ने बयान में कहा कि प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह के पास लागू कानून के मुताबिक इसका अधिकार है कि वे खुद या निवेशकों के माध्यम से इस निर्गम में अतिरिक्त शेयर खरीद सकते हैं।



■ **25,000** करोड़ रुपये का आएगा राइट इश्यू

■ **सिंगापुर का सॉवरिन वेल्थ फंड जीआईसी करेगा 5,000** करोड़ रुपये का निवेश

■ निर्गम के बाद सिंगटेल की एयरटेल में होगी **35.2** फीसदी की प्रभावी हिस्सेदारी



बाजार को मोदी की जीत की उम्मीद : विश्लेषक

विश्लेषकों ने कहा, चुनावी आशावाद की पृष्ठभूमि में मिडकैप शेयरों में हुई हालिया बढ़ोतरी पर बाजार में उतारचढ़ाव बने रहने की संभावना

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 7 मार्च

विश्लेषकों ने कहा है कि बाजार आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत मानकर चल रहा है। चुनाव तक हालांकि शेयरों में उतारचढ़ाव बना रह सकता है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ करने में जुटी हुई हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से बाजार का नजरिया तेजी का बना हुआ है। मार्गन स्टेनली के भारतीय इक्विटी रणनीतिकार रिधम देसाई ने शीला राठी के साथ एक रिपोर्ट में कहा है, चुनाव पूर्व गठबंधन, किसानों को नकद हस्तांतरण की योजना और सीमा पर सैन्य कार्रवाई समेत राजनीतिक मोर्चे पर पिछले आठ हफ्ते के घटनाक्रम आगामी चुनाव में ध्रुवीकरण की वजह बन सकते हैं और ये चीजें मजबूत सरकार की संभावना में इजाफा कर रही हैं।

इस साल अब तक बेंचमार्क सेंसेक्स व निफ्टी-50 सूचकांकों में क्रमशः 1.5 फीसदी व 1.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एसएंडपी बीएसई आईटी, टिकाऊ उपभोक्ता, तेल व गैस, रियल्टी व बैंकेक्स में इस अवधि में 1.9 फीसदी से लेकर 7.8 फीसदी की उछाल आई है।

साल 2014 में आम चुनाव से पहले



‘पिछले आठ हफ्ते के घटनाक्रम आगामी चुनाव में ध्रुवीकरण की वजह बन सकते हैं और ये चीजें मजबूत सरकार की संभावना में इजाफा कर रही हैं’

रिधम देसाई
भारतीय इक्विटी रणनीतिकार, मॉर्गन स्टेनली

बाजार में काफी तेजी दर्ज हुई थी और उस साल चुनाव 7 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1 जनवरी से 7 अप्रैल के बीच सेंसेक्स व निफ्टी में क्रमशः 5.3 फीसदी व 6.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांकों की बढ़त की रफ्तार इस अवधि में क्रमशः 6.8 फीसदी व 9.8 फीसदी रही थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी के निचले स्तर से बाजार में आई उछाल का संबंध आम चुनाव से जुड़े आशावाद से है।



‘शेयर बाजार को नरेंद्र मोदी के सत्ता में लौटने की संभावना ज्यादा दिख रही है’

यू आर भट्ट
प्रबंध निदेशक, डाल्टन कैपिटल

डाल्टन कैपिटल के प्रबंध निदेशक यू आर भट्ट ने कहा, बाजार को इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में लौट रहे हैं। खास तौर से मिडकैप व स्मॉलकैप शेयरों में आई तेजी की एक वजह यही है। जब गठबंधन का निर्माण पूरा हो जाएगा और चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो बाजार ऑपिनियन पोल से आगे की दिशा तलाशेगा। उन्होंने हालांकि कहा कि निफ्टी 11,500 के स्तर को छू सकता है।

तीन-चार महीने में घटेगा आर कैपिटल का कर्ज

म्युचुअल फंड इकाई की हिस्सेदारी विदेशी साझेदार को बेचने, जनरल इंश्योरेंस के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पर टिकी है रिलायंस कैपिटल की योजना

बीएस संवाददाता
मुंबई, 7 मार्च

अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल चार महीने के भीतर अपने बकाया कर्ज में 12,000 करोड़ रुपये तक की कटौती का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह योजना म्युचुअल फंड इकाई की हिस्सेदारी विदेशी साझेदार निपॉन लाइफ को बेचने और सामान्य बीमा इकाई के आईपीओ पर टिकी है।

गुरुवार को रिलायंस कैपिटल ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने अगले तीन से चार महीने में कर्ज में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये की कमी लाने की रणनीति बनाई है। कर्ज में 50-60 फीसदी की भारी कटौती रिलायंस निपॉन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट की 43 फीसदी हिस्सेदारी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की 49 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के अलावा कई गैर-प्रमुख निवेश की बिक्री के जरिए की जाएगी।

अभी रिलायंस कैपिटल का कर्ज करीब 18,000 करोड़ रुपये है।

पिछले महीने रिलायंस कैपिटल ने ऐलान किया था कि वह रिलायंस निपॉन लाइफ की 43 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश अपने साझेदार को की है। इस घोषणा के बाद खबर है कि

घट रही वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री

उद्योग को 15 फीसदी की बढ़त के साथ साल की समाप्ति की उम्मीद

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 7 मार्च

पिछले चार महीने से वाहन उद्योग वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में लगातार गिरावट का सामना कर रहा है, लेकिन उद्योग का कहना है कि इन आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि पिछले साल का आधार काफी ऊंचा था। पिछली दो तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी, उच्च ब्याज दर, ऐक्सल लोड के संशोधित नियमों का क्रियान्वयन, औद्योगिक उत्पादन में नरमी आदि के बावजूद उद्योग को उम्मीद है कि वह ट्रक के मामले में वह साल की समाप्ति कम से कम 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ करेगा।

चौथी तिमाही में नरमी

टाटा मोटर्स के मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री फरवरी में साल दर साल के हिसाब से 18 फीसदी घटी जबकि अशोक लीलैंड की बिक्री इस क्षेत्र में 4 फीसदी घटी। आयशर मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री इस अवधि में क्रमशः 7.8 फीसदी व 17 फीसदी घटी।

टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (वाणिज्यिक वाहन कारोबारी इकाई) गिरीश वाघ ने कहा, उच्च ब्याज दर, ऐक्सल लोड के संशोधित नियम लागू होने, आर्थिक गतिविधियों में नरमी आदि के चलते मांग सुस्त रही और इसका नतीजा वाहनों की बिक्री पर पड़ा। उन्होंने कहा, मध्यम व भारी वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हालांकि घटी, लेकिन सड़क निर्माण, सिंचाई और अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना की पृष्ठभूमि में टिपर के क्षेत्र में 22 फीसदी की मजबूत बढ़त देखने को मिली। डैमलर इंडिया कर्माशियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक व सीईओ सत्यकाम आर्य ने कहा, हमें हालांकि नकदी संकट का कुछ निश्चित असर और ऐक्सल लोड के संशोधित नियम का प्रभाव दिखा, जिसकी वजह से परिवहन की उपलब्ध क्षमता बढ़ गई। इसके



■**कंपनी ने कर्ज में 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये की कमी लाने की रणनीति बनाई है**

■**कर्ज में 50-60 फीसदी की भारी कटौती रिलायंस निपॉन लाइफ ऐसेट मैनेजमेंट की 43 फीसदी हिस्सेदारी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की 49 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के जरिये होगी**

पश्चिम एशिया के तीन सॉवरिन वेल्थ फंड ने रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी लेने में रुचि दिखाई है।

हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया कि जापानी फर्म देश की पांचवीं सबसे बड़ी संपति प्रबंधन

कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। एक सूत्र ने कहा, इस सौदे का विस्तृत ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है। निपॉन लाइफ ने इस सौदे पर सैद्धांतिक मुहर लगा दी है। इस बारे में रिलायंस कैपिटल और निपॉन लाइफ से तत्काल टिप्पणी नहीं मिल पाई। बीएसई पर रिलायंस निपॉन लाइफ का शेयर गुरुवार को 5.3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 195 रुपये पर बंद हुआ।

रिलायंस कैपिटल ने हालिया बयान में कहा है कि रिलायंस निपॉन लाइफ की नियंत्रक हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री बाजार से खासे प्रीमियम पर होने की उम्मीद है। अभी रिलायंस निपॉन लाइफ में रिलायंस कैपिटल व निपॉन लाइफ की हिस्सेदारी 42.9-42.9 फीसदी है, जिसकी वैल्यू 11,918.7 करोड़ रुपये है। सूत्रों ने कहा कि यह सौदा 2019-20 की पहली तिमाही में होने की संभावना है।

इस बीच, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अपने आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी प्रतीक्षा कर रही है। कंपनी ने 8 फरवरी को आईपीओ दस्तावेज दोबारा जमा कराया था क्योंकि पिछली मंजूरी के बाद एक साल की अवधि गुजर गई थी। आईपीओ का आकार 1,500 से 2,000 करोड़ रुपये का हो सकता है।

किक्स के लिए निसान

की सबस्क्रिप्शन योजना

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 7 मार्च

निसान मोटर इंडिया अपनी कारों के लिए सबस्क्रिप्शन मॉडल लागू करने की योजना बना रही है ताकि भारत के यात्री कार बाजार में वह अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। भारतीय यात्री कार बाजार में फिलहाल उसकी सीमित मौजूदगी है। कंपनी ने हाल में उतारे गए कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल किक्स के साथ इस योजना की शुरुआत की है। इस मामले से अवगत दो लोगों ने बताया कि इस योजना के तहत एक मासिक शुल्क के साथ ग्राहक किक्स खरीद सकते हैं। निसान अगले महीने से यह सेवा शुरू करने की योजना बना रही है।

कंपनी के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है। एक ईमेल के जवाब में उन्होंने कहा, 'निसान किक्स के लिए एक नई राह हासिल करने के लिए निसान सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू करेगी। इस पैकेज के तहत शून्य अग्रिम भुगतान के साथ ग्राहक निसान किक्स को अपने घर ले जा सकते हैं।'

प्रवक्ता ने कहा कि मासिक शुल्क में बीमा, रखरखाव और चौबीसो घंटे सड़क किनारे मदद शामिल है। यह योजना किक्स के सभी वेरिएंट्स एवं रंगों पर लागू होगी।

एंड्र्यूरेंस के ओएफएस को 2.5 गुना आवेदन

वाहन कलपुर्जा फर्म एंड्र्यूरेंस टेक्नोलॉजी की 1,200 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री को 2 गुने से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। ऑफर फॉर सेल

पोर्टफोलियो की रणनीति के तौर पर मार्गन स्टेनली को बैंक, डिस्क्रिशनरी कंज्मपशन और इंडट्रियल्स के शेयरों में उचित कीमत पर बढ़त वाले शेयर पसंद हैं और यह लार्जकैप व मिडकैप दोनों क्षेत्रों के हो सकते हैं।

मेबैंक किम इंग सिक्योरिटीज के मुख्य कार्याधिकारी जिगर शाह ने कहा, अगर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो भारतीय जनता पार्टी आगामी आम चुनाव में करीब 250 सीटें जीत सकती है। बाजार अभी इसी को मानकर चलता दिख रहा है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की वापसी की ज्यादा संभावना को देखते हुए बाजार की धारणा कुल मिलाकर सकारात्मक हो रही है, ऐसे में मिडकैप व स्मॉलकैप क्षेत्र के शेयर भी इसी उम्मीद में चढ़ रहे हैं, खास तौर से वे शेयर जिनकी काफी पिटाई हुई थी।

चुनाव के नतीजे को लेकर हालांकि विशेषज्ञों का नजरिया तेजी का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार एकतरफा होगा। हालांकि बाजार में होने वाली गिरावट का इस्तेमाल खरीदारी के लिए किया जाना चाहिए।

क्रेडिट सुइस वेल्थ मैनेजमेंट के शोध प्रमुख (भारतीय इक्विटी) जितेंद्र गोहिल ने कहा, चुनाव से पहले हमें बाजार में भारी उतारचढ़ाव की संभावना नजर आ रही है। हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि अप्रैल-मई 2019 में चुनाव से पहले होने वाला भारी उतारचढ़ाव भारतीय इक्विटी में खरीद का अच्छा मौका मुहैया करा सकता है। मिडकैप के मूल्यांकन में भारी गिरावट को देखते हुए मिडकैप पर हम अपना नकारात्मक नजरिया वापस ले रहे हैं और निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि वे धीरे-धीरे खरीदारी शुरू करें।

करूर वैश्य बैंक

की याचिका

खारिज

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अहमदाबाद पीठ ने गुरुवार को एस्सार स्टील के अधिग्रहण की आर्सेलरमित्तल की बोली का विरोध करने वाली करूर वैश्य बैंक की याचिका खारिज कर दी।

एनसीएलटी पीठ ने अपने आदेश में कहा है, करूर वैश्य बैंक न तो एस्सार स्टील के वित्तीय लेनदार की परिभाषा में आता है, न ही बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से तय समयसीमा के दायरे में केएसएस पेट्रोन पर बकाए का दावा नहीं किया। करूर वैश्य बैंक ने लक्ष्मी निवास मित्तल की अगुआई वाली कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाते हुए केएसएस पेट्रोन पर 3 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाए का भुगतान मांगा था, जिसमें आर्सेलरमित्तल पक्षकार थी। अपनी याचिका में बैंक ने एस्सार स्टील के लिए 42,000 करोड़ रुपये की आर्सेलरमित्तल की बोली को इस आधार पर खारिज करने की मांग की थी कि करूर वैश्य बैंक के बकाए का भुगतान नहीं हुआ है।

बीएस

कंपनी समाचार 3

खुदरा निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। शेयर बिक्री की कीमत 1,100 रुपये तय की गई थी, लेकिन ज्यादातर बोली 1,146 रुपये पर मिली। एक्सचेंज के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

बीएस

4 विविध समाचार

संक्षेप में

आधार सेवा लेने पर 20

रुपये शुल्क देना होगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रत्येक ग्राहक-सत्यान में आधार की सेवाएं लेने पर 20 रुपये और सौदों में धन के लेनदेन की पुष्टि के लिए 50 पैसे शुल्क देना होगा। यूआईडीएआई की विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक ई-केवाईसी में आधार सेवा के लिए 20 रुपये और धन के प्रत्येक लेन देन के समय हां या नहीं की पुष्टि के लिए 50 पैसे का शुल्क लगेगा। यह शुल्क कर सहित होगा। भारत के राजपत्र में जारी इस अधिसूचना के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों और डाकघर को इन शुल्कों से मुक्त रखा गया है।

भाषा

अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर फैसला शुक्रवार को

उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़ा के अलावा अन्य हिन्दू संगठनों ने इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के शीर्ष अदालत के सुझाव का विरोध किया था।

भाषा

जैश ने किए मुशर्रफ के काल में भारत पर हमले

भाषा इस्लामाबाद, 7 मार्च

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने खुफिया एजेंसियों के निर्देशों पर भारत में हमले किए थे। वर्तमान में दुबई में रह रहे 75 वर्षीय मुशर्रफ ने कहा कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

एक

स्थानीय विनिर्माण को मिले प्रोत्साहन

अर्णव दत्ता

नई दिल्ली, 7 मार्च

देश

को दूसरी सबसे बड़ी

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और

उपभोक्ता सामान बनाने वाली

कंपनी एलजी ने स्थानीय टेलीविजन

विनिर्माण को विस्तार देने के लिए

सरकार की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहनों

की कमी को लेकर चिंता जताई है।

कंपनी के नोएडा मुख्यालय के एक

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कुछ अहम

पुर्जों जैसे ओपन सेल और पैनल पर

सीमा शुल्क खत्म किए जाने के साथ

सरकार को विनिर्माताओं को अतिरिक्त

प्रोत्साहन देने की जरूरत है।

यह बयान ऐसे समय में आया है

जब देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता

सामान विनिर्माता फर्म सैमसंग इंडिया

सरकार से बात कर रही है। कंपनी ने

पहले ही अपना टीवी उत्पादन भारत

से वियतनाम स्थानांतरित कर दिया है

और यहां फिर से विनिर्माण शुरू करने

के लिए अतिरिक्त छूट की मांग कर

रही है। सरकार और प्रमुख

विनिर्माताओं के बीच खींचतान पिछले

साल तब शुरू हुई थी जब ओपन सेल

पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत और पैनल

पर शुल्क 7.5 प्रतिशत कर दिया गया

था।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के

चीफ रिलेशनशिप ऑफिसर उमेश ढल

ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि 'जब

तक

भारत में पैनलों और ओपन सेल

के विनिर्माण का माहौल नहीं बन जाता,

इन पर सीमा शुल्क खत्म करके'

स्थानीय स्तर पर विनिर्माण और

आकर्षक बनाया जा सकता है। जब

यह पूछा गया कि आयात शुल्क हटाए

जाने के अलावा एलजी सरकार से और

क्या चाहती है तो उन्होंने आगे कहा

कि सरकार को विनिर्माताओं को

स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के

लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

ढल ने आगे कहा कि टेलीविजन

पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर

कम की जानी चाहिए क्योंकि यह

है और शिक्षित बनाता है।

टीवी सेट पर जीएसटी घटाए जाने

की मांग नई नहीं है। जुलाई 2017 में

जीएसटी पेश किए जाने के बाद से ही

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

दौरान टीवी विनिर्माताओं ने दाम 5 से

7 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

बहरहाल एलजी उत्पादन नहीं रोक

रही है। ढल ने कहा, 'हमारी मेक इन

इंडिया कार्यक्रम में पूरी आस्था है और

हम भारत में उत्पादन जारी रखेंगे। हर

साल हमल लगातार अपनी विनिर्माण

इकाई को मजबूत करने पर निवेश कर

रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा

करना जारी रखेंगे। हम प्रीमियम रेंज

सहित सभी टेलीविजनों का विनिर्माण

भारत में कर रहे हैं।' फर्म अपने नोएडा

और पुणे स्थित संयंत्रों में टीवी का

विनिर्माण करती है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 18

भारी पड़ता लोकलुभावनवाद

एक ओर जहां केंद्र सरकार के आम बजट की प्रस्तुति के बाद उसका जमकर विश्लेषण होता है, वहीं राज्य सरकार के बजट को लेकर कम ही चर्चा होती है। ऐसा तब है जबकि राजस्व और व्यय को लेकर राज्य सरकार के निर्णय, केंद्र सरकार के घाटे और उसकी राजकोषीय गुंजाइश से कतई कम प्रभावकारी नहीं होते। हाल के दिनों

में रूझान एकदम स्पष्ट रहे हैं। 2017-18 तक राज्य सरकारें मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अपने घाटे में एक फीसदी तक का इजाफा कर रही थीं जबकि केंद्र सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर इसमें आनुपातिक कमी कर रही थी। बहरहाल वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों के बजट का विश्लेषण

बताता है कि कई छोटे राज्यों ने रुपये के मौजूदा संदर्भ में अपने घाटे को कम करने का प्रयास किया है। बिहार इस दिशा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। उसने अपने घाटे को 35,000 करोड़ रुपये से कम करके 11,200 करोड़ करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इसके अपवाद भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का घाटा 3,000 करोड़ रुपये बढ़कर 44,000 करोड़ रुपये पहुंच गया। तमिलनाडु ने अपना घाटा 3,300 करोड़ रुपये बढ़ाकर 44,500 करोड़ रुपये पहुंचा लिया जबकि पश्चिम बंगाल का घाटा 6,000 करोड़ रुपये बढ़कर 29,700 करोड़ रुपये हो गया।

यह बात स्पष्ट है कि लोकलुभावन और

चुनावी दबाव इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल का दावा है कि उसने करीब 10 लाख रोजगार तैयार किए हैं लेकिन उसने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। कई राज्यों ने किसानों को आय के हस्तांतरण की घोषणा की है। झारखंड और पश्चिम बंगाल ने एक एकड़ जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार 12 लाख किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपये डाल रही है और उसने भूमिहीन श्रमिकों को 12,500 रुपये देने का वादा भी किया है। तेलंगाना ने किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपये देने का

वादा किया है। अन्य स्थानों पर भी तरह-तरह की ग्रामीण सहायता प्रदान की जा रही है। आंध्र प्रदेश किसानों के कच्चे माल के लिए 5,000 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है। उसने बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस शासन वाले कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफी की जा रही है जबकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। भाजपा शासित एक अन्य राज्य असम में वधुओं को 10 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। सर्वानंद सोनोवाल की सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले राज्य के प्रभावशाली तबके के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए खेल और कला जगत की हस्तियों को आकर्षक राशि देने की घोषणा की है।

वित्त आयोग ने राज्यों के घाटे की भरपाई के नियम सख्त किए हैं। यानी ऐसे व्यय की भरपाई करना अब बहुत जटिल हो गया है। हालांकि राज्य कड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि राजस्व घाटे को शून्य और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी के स्तर के आसपास रखा जाए लेकिन भरपाई के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। यही कारण है कि जिन राज्यों के घाटे में कमी आ रही है उनकी बकाया देनदारी भी बढ़ रही है। ब्याज भुगतान हर वर्ष अधिक राजस्व खा रहा है। जबकि राज्यों को घाटे का लक्ष्य हासिल करने के लिए नकदी अधिशेष बनाए रखना होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह किसी भी दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं है।



अजय मोहंती

मुश्किल दौर से गुजर रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी सहायता में कमी आ रही है। भारत के साथ हालिया तनातनी ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तुरंत विदेशी मदद की जरूरत है लेकिन भारत के साथ जारी टकराव ने उसकी कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। विदेशी मदद के लिए उसके पास मुख्य तौर पर दो रास्ते हैं। पहला चीन और दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)। पाकिस्तान को 2017-18 में कुल जितना विदेशी कर्ज मिला था, उसका 40 फीसदी से अधिक हिस्सा चीन और आईएमएफ से आया था। पाकिस्तान विदेशों से लगभग इतना ही व्यावसायिक ऋण लेता है। इस तरह दोनों माध्यमों से मिलने वाला विदेशी कर्ज पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 30 फीसदी है।

प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा चीन के साथ किए गए सौदों को फिर से खोलने का फैसला किया था। शरीफ ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपैक) के तहत चीन के साथ 62 अरब डॉलर का सौदा किया था। इससे चीन असहज हो गया है क्योंकि इमरान की ज्यादा दिलचस्पी आईएमएफ के राहत पैकेज में है।

यह एक राहत पैकेज होगा क्योंकि रेंटिंग एजेंसी एसएंडपी के आंकड़ों के मुताबिक

पाकिस्तान के पास केवल एक महीने के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय इन आंकड़ों से इतफाक नहीं रखता है। नवंबर में एसेंटेडपी ने पाकिस्तान की दीर्घावधि सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग घटाकर बी से बी माइनस कर दी थी। एजेंसी का कहना था कि पाकिस्तान में आर्थिक विकास की भविष्य लचर है और साथ ही विदेशी और राजकोषीय दबाव भी बढ़ गया है। इस रेटिंग का मतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है।

पिछले सप्ताह पूरे पाकिस्तान में हवाई अड्डे एक दिन से अधिक समय तक बंद रहे। इसके कारण देश को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। दूसरे आंकड़े और भी खराब स्थिति बयां करते हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2017-18 में चालू कीमतों पर आधारित जीडीपी विकास दर के 7.61 फीसदी रहने का अनुमान जताया है लेकिन रेटिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी रुपये में गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर में मापी गई जीडीपी 2019 और 2020 में वास्तव में और सिकुड़ सकती है।

आंकड़ों में इस तरह के बदलाव आईएमएफ ने पाकिस्तान को सख्त

सांख्यिकी प्रणाली में डाल दिया है। आईएमएफ द्वारा इस साल जनवरी में जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक पाकिस्तान ने आखिरकार नैशनल समरी डेटा पेज के जरिये वर्धित सामान्य डेटा प्रसार प्रणाली (ई-जीडीडीएस) की सिफारिशों को लागू कर दिया है।

आईएमएफ ने इससे पहले अंतिम बार जून 2017 में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का सालाना लेखाजोखा खंगाला था। यह एक असामान्य बात थी क्योंकि यह आईएमएफ चार्टर के तहत एक सालाना प्रक्रिया है। सच्चाई यह है कि अधिकांश देशों को तो यह सालाना अनुष्ठान भी गवारा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अलग मिट्टी का बना है। पिछले 30 साल से उसे करीब-करीब हर साल आईएमएफ और विश्व बैंक ने निगरानी को सालाना अनुमति के दायरे से परे जाकर पाकिस्तान की गहराई से पड़ताली की। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12 राहत पैकेज दिए हैं जो एशिया में किसी भी देश को दिए गए सर्वाधिक पैकेज हैं। यही वजह है कि आईएमएफ को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की गहराई से जांच करनी पड़ी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

लेकिन गहन जांच के बावजूद

पाकिस्तान की 13वीं बार राहत पैकेज लेने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान इस साल जनवरी से इसके लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहा है। उसकी नाकामी के दो कारण हैं। इसमें एक चिंता यह है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल चीन के ऋण के भुगतान में कर सकता है। देश के बजट दस्तावेजों के मुताबिक यह राशि 10.8 अरब डॉलर है। कार्यकारी बोर्ड के आकलन में कहा गया है, ‘बाहरी दबावों, समायोजन मौद्रिक रुख और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ज्यादा आयात के कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति डांवाडोल हुई।’ दूसरे शब्दों में आईएमएफ ने इस बात की गारंटी मांगी है कि उसके और चीन के कर्ज को आपस में नहीं मिलाया जाएगा। पाकिस्तान ने 27 देशों से कर्ज ले रखा है।

दूसरा कारण यह है कि आईएमएफ पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि वह अतिरिक्त राजस्व उपायों से राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करे और खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करे। लेकिन वह सामाजिक योजनाओं के लिए खर्च जारी रख सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे रक्षा खर्च में कटौती करने को कहा गया है जो उसके सालाना बजट का 20 फीसदी से भी अधिक है। भारत में रक्षा खर्च बजट का 11 फीसदी है। पिछले सप्ताह भारत के साथ तनातनी के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने बजट में से एक निश्चित राशि निकाली है।

आईएमएफ ने साथ ही पाकिस्तान स्टेट बैंक को मुद्रास्फीति के जोखिमों और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय करने को कहा है लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। विदेशी मुद्रा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता पैदा करती है जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। चूंकि पाकिस्तान को 50 फीसदी बाहरी कर्ज बाजारों से जुटाना है, इसलिए उसे कर्जदाताओं को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा ताकि उनकी पाकिस्तान में दिलचस्पी बनी रहे।

पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की भारी कमी है और यही वजह है कि उसने इसे बढ़ाने के लिए नए-नए उपाय करने शुरू कर दिए हैं। वह उन गिने चुने देशों में से एक है जहां मजदूरों को बाहर भेजने के लिए एक अलग मंत्रालय है। सरकार मजदूरों को खाड़ी सहित विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों को तलाशने में मदद करती है। इसके लिए अलग से बने मंत्रालय के पास 600,000 से अधिक लोगों के आंकड़े हैं। पाकिस्तान की एक और नीति तंबाकू को बढ़ावा देने की है। उसके वित्त मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसने तंबाकू के बीजों के निर्यात और विश्लेषण के लिए फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि विश्लेषण रिपोर्ट से भविष्य में देश में अच्छी गुणवत्ता के तंबाकू के उत्पादन में मदद मिलेगी और इसका निर्यात किया जा सकेगा।

बजट में विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों के लिए एक लॉटरी का प्रस्ताव है। इसके तहत अगर वे वैध माध्यमों से स्वदेश पैसा भेजते हैं तो मासिक लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र के समग्र सुधार के लिए कर्ज माफी नाकाफी

किसानों को कर्ज माफी या आय समर्थन जैसी चैरिटी की जरूरत नहीं है। किसानों के राष्ट्रीय संगठन भारतीय कृषक संघ कंसोर्टियम (सीफा) का कहना है कि 'किसानों को सम्मान के साथ जीने के लिए अपनी उपज पर वाजिब प्रतिफल से होने वाली कमाई की जरूरत है।' यह संगठन अन्य कृषि समूहों की तुलना में अलग राय रखता है। अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कृषक संगठनों की तरह यह समूह किसानों का कर्ज माफ करने और दूसरे वित्तीय अनुदानों की मांग नहीं कर रहा है। सीफा की मांगें गैर-राजनीतिक होने के साथ ही कृषि को अपने आप में सक्षम बनाने वाली नीतियां बनाने से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सीफा दूसरे कृषि संगठनों की तरह जीन-संवर्द्धित (जीएम) फसलों का विरोध करने के बजाय कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल का पक्षधर है। वह कृषि कार्य को लाभदायक बनाने के लिए नैनो, अंतरिक्ष, नाभिकीय, सूचना एवं जैव-प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के पक्ष में है। इस तरह सीफा का अभियान मूलतः तकनीक एवं ज्ञान पर आधारित कृषि विकास को लेकर है जिसमें कारगर मार्केटिंग हो और किसानों को केंद्र में रखते हुए नीतियां बनाई जाएं।

इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सीफा ने विस्तृत राष्ट्रीय कृषि एजेंडा तैयार किया है और अगले 10 वर्षों तक सरकार से इस पर चलने का अनुरोध करता है। इसका व्यापक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सालाना 4 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करना है जो फिलहाल 2-3 फीसदी ही है। ऐसा होने पर कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के बीच वृद्धि दर का फासला कम हो सकेगा। इसके लिए कृषि को आर्थिक विकास के केंद्र में रखने की जरूरत है। कुछ उसी तरह जिस तरह आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही उद्योग, व्यापार, सेवाएं एवं दूसरे क्षेत्रों को अहमियत दी जाती रही है। सीफा कृषि मंत्री को उप प्रधानमंत्री को दर्जा देने के साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की भी बात करता है। इस एजेंडे में कृषि की जिम्मेदारी उन अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है जो खेती के बारे में थोड़ी-बहुत समझ रखते हों।

सीफा के इस एजेंडे में उन बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया



खेती-बाड़ी

सुरिंदर सूद

कृषि उत्पादों के विदेशी कारोबार पर लगने वाले शुल्क का ढांचा ऐसा हो कि निर्यात को प्रोत्साहन मिले और केवल आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किया जाए। आयातित उत्पादों की भारत आने के बाद लागत घरेलू उत्पादों के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम-से-कम 10 फीसदी अधिक हो ताकि शुल्क नीय उपज पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। आवश्यक वस्तु अधिनियम को भी संशोधित करने की जरूरत है ताकि व्यापक उपभोग वाले कृषि उत्पादों के व्यापार पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकें।

सीफा का एक और उल्लेखनीय प्रस्ताव यह है कि कृषि एवं सिंचाई को संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाए जिससे केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों के विकास में अधिक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिले। वैसे इस प्रस्ताव पर अमल कर पाना काफी मुश्किल है। कृषि क्षेत्र को ऋण आवंटन, फसल बीमा, आपदा राहत, विदेश व्यापार और तकनीक प्रोत्साहन जैसे कई अहम मुद्दों को केंद्र सरकार को काफी हद तक देख रही है। राज्य सरकारें तो बीज, बिजली, सहकारी समितियों और कृषि संबद्ध सेवाओं की ही देखभाल करती हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश क्षेत्रों की हालत खस्ता है। राज्यों की खराब आर्थिक सेहत के चलते सिंचाई क्षेत्र में फंड का अभाव रहता है। ऐसे में अगर सिंचाई को समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है तो केंद्र की सीधी निगरानी में रहने से उसे भी काफी लाभ होगा।

आम चुनावों को करीब आते देख सीफा विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। उपरोक्त क्षेत्रीय दलों से उसे अधिक उम्मीदें हैं। भविष्य में क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम होने की संभावना के चलते सीफा उससे अपने चुनावी घोषणापत्र में इन बिंदुओं को जगह देने का अनुरोध कर रहा है। ये दल अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें इससे फायदा ही होगा क्योंकि सीफा के अधिकांश सुझाव न केवल सोचे-समझे हुए हैं बल्कि वे नतीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

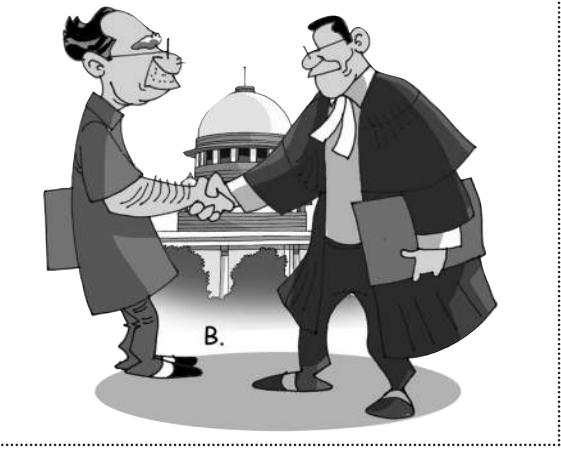
कानाफूसी

राज्यसभा का लालच!

तमिलनाडु के दो प्रमुख द्रविड़ राजनीतिक दल जुलाई में खाली होने जा रही राज्यसभा सीटों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन के औजार के रूप में कर रहे हैं। जून में छह राज्यसभा सदस्यों की सीट खाली होने जा रही है और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कणम और द्रविड़ मुन्नेत्र कणम दोनों ने अपने छोटे साझेदारों पट्टािल मक्कल काची और मरुमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कणम को एक-एक सीट की पेशकश की है। चूंकि तमिलनाडु विधानसभा में 21 सीट खाली हैं इसलिए इन वादों का पूरा होना काफी हद तक इन सीटों के उपचुनाव नतीजों पर निर्भर करेगा। इस बीच अभिनेता से राजनेता बने विजयकान्त की देशीय मुरपोक्कु द्रविड़ कणम ने शायद इन दोनों में से किसी दल के साथ गठजोड़ में देरी इसलिए की क्योंकि उसे राज्यसभा सीट की पेशक

व्यवहार बरकरार

राफेल सौदे को लेकर समीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार और याचियों के बीच गरमागरम बहस के बावजूद दोनों दलों के बीच पेशेवर व्यवहार में कोई कमी नहीं आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी भी इस मामले में एक याची हैं। उन्हें दीपहर के भोजन के पश्चात प्रधान न्यायाधीश के कक्ष में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के साथ हाथ मिलाते देखा गया। उसके बाद के सत्र में सरकार ने याचियों पर सरकारी गोपनीयता कानून के अधीन कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा कि जिन दस्तावेजों पर वह याचिका दाखिल की गई है, वे रक्षा मंत्रालय से चुराए गए हैं।



आपका पक्ष

दिल्ली में आप और कांग्रेस की राह जुदा

कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर आप के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है। दरअसल कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने का आग्रह किया था। दिल्ली की प्रदेश इकाई आप पार्टी से किसी तरह के गठबंधन का विरोध कर रही थी जिसे देखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आप से गठजोड़ नहीं करने का निर्णय किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस और आप के बीच मतों के विभाजन से इस बार भी



सकता है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक बयानबाजी आम जनता की समझ से बाहर होती जा रही है। राजनीति में कदम रखते हुए वे बार-बार कांग्रेस और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस लगातार उनके निशाने पर रही और अब लोकसभा चुनाव के

कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है

सामने आते ही वह कांग्रेस से गठबंधन की बात करने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस द्वारा गठबंधन से इनकार करने पर वे फिर पुरानी बोली बोलने लगे और

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।

कहा कि कांग्रेस भाजपा विरोधी मतों को विभाजित कर भाजपा की मदद कर रही है। हालांकि स्पष्ट हो गया कि भाजपा, कांग्रेस और आप अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। आम जनता चुनावों में इन दलों का राजनीतिक भविष्य तय करेगी लेकिन पार्टियों को इस बात ध्यान रखना चाहिए कि उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है और कहीं चुनाव जीतने के लिए वे अपनी ही विचारधारा से अलग राह पर तो नहीं जा रहे।

नफीसा, नई दिल्ली

ई-कॉमर्स में जियो की दस्तक
खबर है कि दीपावली के मौके पर रिलायंस जियो ई-कॉमर्स क्षेत्र में धमाकेदार दस्तक की तैयारी कर रही है। अभी तक फ्लिपकार्ट बिग

बिलियन डे और एमेज़ॉन इंडिया अपने ग्रेट इंडियन दीवाली सेल के जरिये एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती रही है। ऐसे में जियो के इस क्षेत्र में आने से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। आरआईएल ई-कॉमर्स कारोबार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है और कंपनी अक्टूबर-नवंबर में देश भर में ई-कॉमर्स सेवा शुरू कर सकती है। कंपनी इसके लिए मुंबई, कोलकाता, और बेंगलूर सहित छह शहरों में परीक्षण भी कर रही है। रिलायंस असंगठित क्षेत्र के स्टोर और कुछ बड़े रितिलरों के यहां जियो ब्रांड के प्लाइट ऑफ सेल्स मशिनों लगा रही हैं। इसके जरिये कंपनी लेनदेन के डेटा को जियो सिस्टम के साथ जोड़ देगी। इसके अलावा आरआईएल टेलीकॉम, मीडिया और कॉमर्स क्षेत्र को आपस में मिलाने की तैयारी कर रही है। इससे मौजूदा कंपनियों में एक तरह की खलबली मच गई है। आने वाले समय में जियो के विस्तार पर कंपनियों और कारोबारियों, सभी की निगाहें होंगी।

6 जिंस कारोबार

संक्षेप में

जनवरी में घटा भारत से चाय का निर्यात

देश से चाय निर्यात जनवरी 2018 के दो करोड़ 38 लाख किलोग्राम के मुकाबले जनवरी 2019 में मामूली रूप से घटकर दो करोड़ 23 लाख किलोग्राम रह गया। चाय बोर्ड के प्रारंभिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। चाय का प्रति किलोग्राम इकाई मूल्य जनवरी 2018 के 197.42 रुपये से बढ़कर 215.88 रुपये प्रति किलोग्राम होने की वजह से जनवरी 2019 में चाय निर्यात मूल्य पहले के 470.83 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 480.77 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। गंतव्य के हिसाब से राष्ट्रमंडल देशों को निर्यात जनवरी 2019 में भारी गिरावट के साथ 49.6 लाख किलोग्राम रह गया जबकि पिछले साल के इसी महीने में 60.6 लाख किलोग्राम निर्यात हुआ था।

कपड़ा क्षेत्र में कर छूट के लिए योजना मंजूर

कपड़ा क्षेत्र में निर्यात के लिए परिधानों और मेड-अप टेक्सटाइल (चादर, कंबल, पर्दे) इत्यादि को केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्निहित करों के भार से मुक्त करने की एक योजना को मंजूरी दी। इससे निर्यात बाजारों में देश के कपड़ा उद्योग को प्रतियस्धी बनाए रखने में मदद मिलेगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। वर्तमान में राज्य सरकारें जोएफटी के अलावा भी स्टांप शुल्क, पेट्रोलियम कर, बिजली शुल्क और मंडी शुल्क के रूप में कई तरह के अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाती हैं जिनका कपड़ा क्षेत्र पर बोझ पड़ता है।

भाषा

भाषा

चीनी मिलों को तोहफा : एथनॉल के लिए सस्ते ऋण को कैबिनेट की स्वीकृति

15,500 करोड़ रु. का कर्ज मंजूर

बीएस संवाददाता /एजेंसियां
नई दिल्ली, 7 मार्च

चीनी मिलों में एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने

गुरुवार को 15,500 करोड़ रुपये के दूसरे सस्ते ऋण (सांपट लोन) को मंजूरी प्रदान की। आसान शर्तों पर दिए जाने वाले इस ऋण पर सरकार 3,355 करोड़ रुपये का कुल ब्याज का वहन करेगी।

इसमें 2,600 करोड़ रुपये का सस्ता ऋण भी शामिल है जो शीरा-आधारित डिस्टिलरियों को क्षमता वृद्धि और नई इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जाएगा। जून 2018 में सरकार ने 4,400 करोड़ रुपये के सस्ते ऋण की घोषणा की थी और पांच साल की अवधि के लिए चीनी मिलों को 1,332 करोड़ रुपये की ब्याज छूट मुहैया कराई थी। इसमें एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है।

अब तक खाद्य मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपये के ऋणों के लिए 114 आवेदन स्वीकार किए हैं जबकि 13,400 करोड़ रुपये के सस्ते ऋणों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, 'एथनॉल क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त कोष को मंजूरी दी है। ये अतिरिक्त कोष दो श्रेणियों – 2,790 करोड़ रुपये और 565 करोड़ रुपये– में होंगे।'

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कोष चीनी क्षेत्र में वित्तीय दबाव दूर करने के सरकार के उपायों का हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'चीनी मिलों पर बकाया बरकरार है जिससे उनका दबाव बढ़ रहा है। सरकार रुपये से अधिक के ऋणों की पिछली मंजूरी के साथ, 15,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋणों से देश में अन्य 300–400 करोड़ लीटर एथनॉल क्षमता के निर्माण में मदद मिल सकती है।'

जेटली से जब यह पूछा गया कि क्या सांपट लोन



चीनी उद्योग

■ एथनॉल क्षमता वृद्धि के लिए जून में **4,400** करोड़ रुपये का पहला सस्ता ऋण मंजूर किया गया था

■ इसमें से लगभग **2,600** करोड़ रुपये का सस्ता ऋण शीरा-आधारित प्रमुख डिस्टिलरियों के लिए निर्धारित है

से गन्ना बकाया का बोझ घटाने में मदद मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि इसका तुरंत कोई असर नहीं दिखेगा, लेकिन दीर्घावधि में ऐसा सब होगा। इस विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के फरवरी तक गन्ना बकाया 20,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। खाद्य मंत्रालय शीरा-आधारित प्रमुख डिस्टिलरियों के लिए एक अलग योजना तैयार करेगा। जून 2018 में सीसीईए द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ब्याज राशि सालाना 6 प्रतिशत या बैंकों द्वारा वसूले जाने वाली ब्याज की वाणिज्यिक दर के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) पर देय होगी। भारतीय चीनी मिल संगठन (इस्मा) के महानिदेशक अबिनाश वर्मा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, 'सितंबर 2018 में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों की पिछली मंजूरी के साथ, 15,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋणों से देश में अन्य 300–400 करोड़ लीटर एथनॉल क्षमता के निर्माण में मदद मिल सकती है।'

उन्होंने कहा कि 355 करोड़ लीटर की मौजूदा एथनॉल क्षमता को देखते हुए देश में अगले साल पेट्रोल के साथ इसके मिश्रण की मात्रा 10 प्रतिशत को पार कर जाने का अनुमान है।

गन्ने से तैयार एथनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिश्रण के लिए किया जाएगा और इससे गन्ना किसानों को अपनी कृषि क्षमता का उचित मूल्य मिलेगा। पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण से देश को अपना तेल आयात घटाने में भी मदद मिलेगी।

इस महीने के शुरू में, सीसीईए ने चीनी मिलों के लिए 8,000–10,000 करोड़ रुपये के सांपट लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से चुकाया जाएगा। ये ऋण एक साल के लिए 7–10 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिए जाएंगे और इसके लिए सरकार 553–1,054 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी स्वयं वहन करेगी। यह ऋण प्रत्यक्ष रूप से किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।

नई दिल्ली | 8 मार्च 2019 शुक्रवार

बिजनेस स्टैंडर्ड

एमसीएक्स का कपास वायदा रिकॉर्ड स्तर पर

बीएस संवाददाता

मुंबई, 7 मार्च

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) पर कपास का वायदा कारोबार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक्सचेंज में कपास स्टॉक पिछले रिकॉर्ड स्तर से करीब 56 फीसदी अधिक रहा है। एक्सचेंज का दावा है कि बेहतर तकनीक और कारोबार में पारदर्शिता के कारण कपास वायदा अनुबंध में जिनर, कॉरपोरेट, व्यापारियों और किसानों जैसे हितधारकों की प्रतिभागिता लगातार बढ़ी है जिसके कारण स्टॉक और कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

एक्सचेंज द्वारा भेजी गई जानकारी के मुताबिक एमसीएक्स से मान्यता प्राप्त गोदामों (वेयरहाउसों) में 5 मार्च, 2019 तक 1,81,200 गांठ का नया सर्वकालिक अधिक स्टॉक मिश्रण की मात्रा 10 प्रतिशत पिछले साल की इसी अवधि की 1,16,300 गांठ से 55.80 फीसदी अधिक है। इसके अलावा कपास वायदा अनुबंध में 22 फरवरी, 2019 को इंट्रा-डे कारोबार में दूसरी सबसे अधिक मात्रा 3,70,700 गांठ दर्ज हुई जिसकी कीमत तकरीबन 764 करोड़ रुपये बैठती है। जबकि इसी दिन ओपन इंस्ट्रेस्ट 4,30,400 गांठ के स्तर पर पहुंच गया था। अक्टूबर 2011 में जब से एमसीएक्स का वायदा कारोबार अनुबंध शुरू हुआ तब से अब तक 15.44 करोड़ से अधिक गांठ के सौदे दर्ज हुए हैं। इन सौदों में घरेलू हेजर्स की बढ़ती प्रतिभागिता यह दर्शाती है कि कपास अनुबंध विभिन्न हितधारकों की जोखिम प्रबंधन की

आवश्यकता पूरा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तकनीकी विशिष्टता वाले इस अनुबंध की डिलिवरी का दायरा भारत की कपास फसल के 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय कपास संघ (सीएआई) के उपाध्यक्ष और मंजीत कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बीएस राजपाल ने कहा कि एमसीएक्स के मान्यता प्राप्त वेयरहाउसों में सबसे अधिक कॉटन का भंडारण एक बार फिर प्रतिभागियों को डिलिवरी देने और प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज की सुसज्जित और मजबूत वेयरहाउसिंग और डिलिवरी तंत्र में कपास के हितधारकों के विश्वास की पुष्टि करता है।

कपास में 11 प्रतिशत गिरावट का अनुमान

कुल कपास उत्पादन वर्ष 2018–19 के दौरान 11 प्रतिशत घटकर 328 लाख गांठ (एक गांठ= 170 किलोग्राम) रहने का अनुमान है। भारतीय कपास संघ (सीएआई) ने गुरुवार को कहा कि उत्पादन में संभावित गिरावट मुख्य रूप से कई प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण है। सीएआई के अध्यक्ष अतुल गणन ने कहा कि पिछले सत्र में कुल कपास उत्पादन 365 लाख गांठ रहा। इस वर्ष लगभग 123 लाख हेक्टेयर में कपास बुआई हुई है। विशेष रूप से गुजरात जैसे राज्यों में 28 प्रतिशत बारिश की कमी है। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी बारिश की कमी रही है।

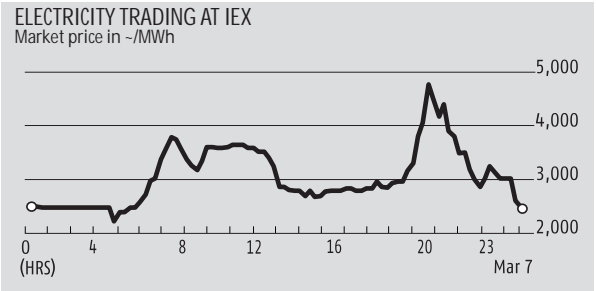
भाषा

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव				
As on Mar 7	International Price	%Chg*	Domestic Price	%Chg*
METALS (\$/tonne)				
Aluminium	1,846.0	-5.9	2,156.8	-3.3
Copper	6,505.0	5.4	6,841.9	1.8
Nickel	13,610.0	25.8	13,926.6	19.5
Lead	2,090.5	6.4	2,228.3	3.1
Tin	21,575.0	14.0	23,996.6	21.8
Zinc	2,801.5	3.4	3,128.1	1.6
Gold (\$/ounce)	1,286.1*	3.0	1,420.5	4.1
Silver (\$/ounce)	15.1*	3.1	16.8	4.5
ENERGY				
Crude Oil (\$/bbl)	66.3*	10.0	65.4	10.4
Natural Gas (\$/mmbtu)	2.8*	-37.0	2.8	-37.8
AGRI COMMODITIES (\$/tonne)				
Wheat	209.8	-4.5	271.4	-9.3
Maize	192.6*	-2.9	221.4	-0.3
Sugar	337.4*	-2.4	468.5	4.1
Palm oil	530.0	11.6	883.7	7.6
Rubber	1,678.3*	34.2	1,821.2	8.4
Coffee Robusta	1,516.0*	-1.1	1,864.0	-7.7
Cotton	1,610.5	-8.9	1,766.1	-3.0

* As on Mar 7, 19 1800 hrs IST, % Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.0& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LUFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous day price.
2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket.
4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MXX near month futures.
5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LUFF E future prices of near month contract.
6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-100M near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price.
7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices.
8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price.
9) International Cotton no. 2-NYBOT near month future & domestic cotton is MXX future prices near month futures.

Bloomberg chartMaker Compiled by BS Research Bureau



जिंस वायदा

बुलपिन की कीमतों में घट-बढ़ के सामने प्रबंधन और सुरक्षा प्राप्त करें एमसीएक्स पर हेज करें



Name Exchange (Units)				
Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCK(1 B)				
Mar 29	20930, 21300, 20920, 21020.....	6526	931	55561
Apr 30	21270, 21340, 21220, 21310.....	4150	538	16250
May 31	21500, 21600, 21500, 21570.....	570	69	587
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Mar 19	1968.5, 1971, 1953.5, 1959.....	32050	1779	35730
Apr 16	4205, 4215, 4188, 4193.5.....	39140	2259	79240
May 20	2028, 2028, 2012, 2019.....	860	80	6720
Jun 20	2062.5, 2064, 2050, 2055.....	160	15	2410
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1125.5, 1129.5, 1122, 1127.5.....	1470	711	11863
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 16	1660, 1665, 1660, 1665.....	100	5	1490
Guar Seed 10 MXX(1 Q)				
Mar 19	4150, 4159, 4133.5, 4139.....	27380	1485	31520
Apr 16	4205, 4215, 4188, 4193.5.....	30580	1784	83840
May 20	4256, 4264, 4242.5, 4252.5.....	1430	99	4200
Maize-Gulabagh NCDEX(1 Qt)				
Mar 19	1677, 1697, 1660, 1697.....	110	11	370
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qt)				
Mar 19	5140, 5190, 5136, 5186.....	26575	1743	56080
Apr 16	5256, 5266, 5210, 5264.....	33320	2247	113345
May 20	5300, 5340, 5300, 5338.....	945	86	28670
Jun 20	5378, 5378, 5378, 5378.....	100	4	715
Crude Palm Oil MCK(10 K)				
Mar 29	549.9, 549.9, 541.9, 542.6.....	4620	345	52300
Apr 30	552, 552.5, 547, 548.2.....	1810	130	21410
May 31	555.5, 555.5, 550.9, 551.9.....	470	35	1140
Mentha Oil MCK(1 K)				
Mar 29	1612, 1624, 1603, 1620.7.....	182.88	446	261.36

Name Exchange (Units)				
Maturity	Open, High Low Close	Qty		
Apr 30	1539, 1549, 1529, 1543.9.....	8.64		
May 31	1315, 1316.9, 1310.1, 1314.....	1.08		
Jun 28	1197.2, 1214, 1193.5, 1208.9.....	6.84		
Jul 31	1235.9, 1235.9, 1235.9, 1235.9.....	0.36		
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Apr 16	3810, 3828, 3807, 3824.....	11230		
May 20	3850, 3867, 3845, 3865.....	3280		
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Mar 19	764.75, 764.75, 759.75, 761.05.....	10270		
Apr 16	746.75, 746.75, 739.65, 741.7.....	7850		
May 20	735, 736.5, 732.1, 733.05.....	1450		
Jun 20	733.5, 733.5, 730, 730.....	180		
Jul 19	729, 727, 729, 729.....	10		
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Mar 19	3693, 3700, 3660, 3665.....	40140		
Apr 16	3755, 3757, 3707, 3715.....	49100		
May 20	3815, 3820, 3765, 3772.....	10620		
Jun 20	3862, 3862, 3820, 3837.....	1370		
Others				
Guar(Gum ST-Jodhpur NCDEX(1 Qt)				
Mar 19	8290, 8334, 8270, 8325.....	8805		
Apr 16	8390, 8449, 8377, 8441.....	10915		
May 20	8506, 8550, 8506, 8526.....	260		
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qt)				
Mar 19	4148, 4167, 4123, 4134.....	15310		
Apr 16	4195, 4213, 4165, 4177.....	22670		
May 20	4233, 4256, 4210, 4217.....	2010		
Jun 20	4275, 4300, 4263, 4281.....	120		
Wheat-Kota NCDEX(1 Qt)				
Mar 19	1900, 1900, 1900, 1900.....	20		
Apr 16	1862, 1862, 1850, 1850.....	60		
Spices				
Cardamom MCK(1 K)				
Mar 15	1560.1, 1565, 1560, 1561.3.....	2.3		
Apr 15	1486, 1498.8, 1481.6, 1488.7.....	0.6		
Coriander Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 16	6178, 6264, 6150, 6248.....	6260		
May 20	6251, 6332, 6220, 6309.....	1260		
Jun 20	6327, 6327, 6327, 6327.....	120		
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 19	15525, 15535, 15365, 15410.....	1131		
Apr 16	15435, 15445, 15195, 15245.....	2295		
May 20	15520, 15520, 15345, 15405.....	780		
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 16	6396, 6398, 6324, 6342.....	1060		
Apr 20	6424, 6432, 6372, 6402.....	345		
Jun 20	6430, 6430, 6430, 6430.....	5		
धातु				
Metal- ferrous				
NICKEL MCK(1 K)				
Mar 29	952, 952, 937.6, 939.4.....	1398.7		
Apr 30	954.1, 954.1, 943.2, 945.1.....	57.5		
Metal- non ferrous				
Aluminium MCK(1 K)				
Mar 29	144.05, 144.35, 143.6, 143.8.....	8785		

बिज़नेस स्टैंडर्ड सालाना इंश्योरेंस राउंड टेबल-2019



फोटो: कमलेश पेडणेकर

बाएं से दाएं: एचडीएफसी लाइफ के कार्यकारी निदेशक सुरेश बादामी, बजाज आलियांज लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ तरुण चुघ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ एनएस कन्नन, बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक तमाल बंधोपाध्याय, पॉलिसीबाजार के सीईओ यशीश दहिया, आदित्य बिडला सन लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ पंकज राजदान और एसबीआई लाइफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव नौटियाल

युवा चुनता है बेहतरीन योजना

छह शीर्ष बीमा अधिकारियों ने युवा ग्राहकों (मिलेनियल) और उनके व्यवहार पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे गलत तरीके से योजनाएं बेचने के मामले कम हुए हैं और आखिर क्यों पहुंच का स्तर कम हुआ है।

मिलेनियल ग्राहकों को आकर्षित करने के तरीके

संजीव नौटियाल: मिलेनियल ग्राहक जीवन बीमा कंपनियों के साथ मिलकर योजनाएं नए सिरे से तैयार करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन बीमा उद्योग लचीला हो और भागीदारी वाला हो। हमारे यहां कहीं अधिक व्यवस्थित योजनाएं हैं लेकिन ग्राहक चाहता है कि वह उनमें बदलाव कर सके। मिलेनियल ग्राहक स्पष्ट और ईमानदारी से किए गए संवाद को तबज्जो देते हैं। बीमाकर्ताओं को इस बात को ध्यान में रखकर काम करना होगा। योजनाओं को सहज बनाना महत्वपूर्ण है और ऐसा किया जाना चाहिए। इन ग्राहकों की सेवा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण व्यवस्था को पारदर्शी रखा जाना चाहिए।

सुरेश बादामी: हमें मिलेनियल ग्राहकों की खर्च और खपत की अलग आदत और ब्रांड की उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए यह देखना चाहिए कि हम उनके लिए क्या मूल्य तैयार कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मिलेनियल ग्राहक किसी एक योजना के बजाय समूचे माहौल को तबज्जो

देते हैं। हमें उनके लिए पूरा समर्थन देने वाली व्यवस्था तैयार करनी होगी।

एन एस कन्नन: यह एक विविधतापूर्ण आबादी है जिसे खांचों में बांधकर नहीं देखा जा सकता है। हमें उनके लक्ष्य को जानकार उनकी रुचि के हिसाब से बात करनी होगी। हमारी टर्म योजनाओं में से करीब 50 फीसदी ऐसे ही ग्राहक लेते हैं और यह बहुत अच्छा वर्ग है। हमें साझेदारी और अपारंपरिक वितरण के लिए तैयार रहना चाहिए। खरीद की प्रक्रिया सहज होनी चाहिए वरना वे दूर हो जाएंगे। पॉलिसी तत्काल जारी होनी चाहिए।

यशीश दहिया: मिलेनियल ग्राहक अपना शोध स्वयं करते हैं, उन्हें क्या चाहिए यह चिन्हित करते हैं और किसी के कहने के बजाय अपने शोध पर यकीन करते हैं। उनका स्वभाव सवाल करने का होता है और वे योजना चयन में बेहतर होते हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि उनमें से अधिकांश दीर्घावधि के निवेश की दृष्टि से नहीं सोचते। वे लॉक इन अवधि को लेकर सवाल करते हैं और अधिक आजादी चाहते हैं।

जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम का अनुपात घट क्यों रहा
पंकज राजदान: अगर आप वर्ष 2010 से तुलना करें तो वही योजनाएं करीब 20-

25 प्रतिशत सस्ती दर पर बिक रही हैं। जीवन बीमा नियामकीय बदलावों की वजह से सस्ता हुआ है और पहुंच भी आसान हुई है। हमें इस क्षेत्र पर जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में नहीं बल्कि कुल घरों की संख्या के संदर्भ में दृष्टि डालनी चाहिए। आबादी का एक बड़ा हिस्सा बीमा कराता है लेकिन वह अपर्याप्त है।

तरुण चुघ: निजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप नॉर्मिनल जीडीपी को 10-12 फीसदी मानें और निजी क्षेत्र की वृद्धि दर 14 फीसदी है तो बीमा क्षेत्र का विकास धीमी गति से हो रहा है। इसका दायरा बहुत व्यापक है इसलिए भी तेज गति से विकास मुश्किल है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो धीरे-धीरे हमसे दूर गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं हल कर पा रहे।

नौटियाल: एक वक्त था जब ढेर सारी यूलिप की बिक्री हुई। उसकी वजह से पहुंच बहुत बढ़ गई थी लेकिन उसके बाद नियामक ने उन्हें रोक दिया और इसमें गिरावट आने लगी। क्षणिक तेजी के बाद स्थिरता आ गई। बीते तीन चार वर्ष में स्थिर गति से वृद्धि हुई है।

गलत बिक्री बादामी: लंबे समय तक जीवन बीमा अपनी जटिलता के कारण ऐसी योजना थी जिससे बेचना पड़ता था। नए नियमन,

तकनीक और डिजाइन की वजह से लोग तुलना करने और योजनाओं के असर को समझने लगे हैं। जीवन बीमा में समझ को लेकर कुछ कमी है लेकिन उद्योग जगत ने भी नियंत्रण कायम किए हैं।

चुघ: गलत तरीके से योजनाएं बेचना कम हुआ है। यहां तक कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी सीएजीआर में भी हर वर्ष 22-23 फीसदी की कमी आ रही है। एक वक्त था जब हर कोई गलत योजना बेचता था। नियामक ने कंपनियों में भरोसा जताया और हालात में सुधार हुआ। वह अतीत की बात हो गई लेकिन कलंक तो अब तक है। नकदीकरण को लेकर भी कई मसले हैं जिनके कारण लोग योजनाओं की गलत बिक्री की चर्चा करते हैं।

राजदान: जहां भी पैसा शामिल होता है, गलत योजनाओं की बिक्री की जाती है। मामला बढ़ने पर नियामक ने सख्त रुख अपनाया और उसके बाद इन मामलों में उल्लेखनीय कमी आई।

कन्नन: योजनाओं की गलत बिक्री से हमें मदद नहीं मिलती। हमें इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि अंशधारक के लिए मूल्य खराब ही होता है। कंपनियों को इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नियामक के साथ मिलकर इसका विरोध किया जाना चाहिए और यही हुआ भी। बीते पांच वर्ष में प्रीमियम के नवीनीकरण में सुधार की गति इसका उदाहरण है। अगर गलत योजनाएं बेची जातीं तो लोग प्रीमियम का नवीनीकरण नहीं करते।

‘तिमाही आधार पर नहीं हो सकता सामान्य बीमा क्षेत्र का आकलन’



सामान्य बीमा क्षेत्र की पांच कंपनियों के प्रमुख इस उद्योग के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं और उन्हें हालात सुधरने की भी उम्मीद है।

सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य (जनरल) बीमा कंपनियों की हालत में सुधार

एलिस वैद्यन: आपको यह देखना होगा कि सरकारी नियंत्रण वाली सामान्य बीमा कंपनियों ने देश की सेवा किस तरह की है और समय के साथ किस तरह उनका विकास हुआ है ? हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि सार्वजनिक बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 55 फीसदी से घटकर 45 फीसदी पर आ चुकी है। शायद तीन कंपनियों के विलय की घोषणा से लोगों के बीच अधिक भरोसा नहीं पैदा हुआ। जहां तक हमें पता है, विलय की प्रक्रिया जारी है।

वरुण दुआ: भारत करीब 20-30 दस्तों से बना हुआ है। इस देश में ऐसे इलाके हैं जहां सार्वजनिक बीमा कंपनियां अपनी सेवाएं दे सकती हैं जबकि निजी बीमा कंपनियां या तो वहां कभी नहीं जाएंगी या बहुत देर से जाएंगी। ऐसे में यह हो सकता है कि हमारी तरह की कंपनियां डिजिटल इंडिया और नई सदी के ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों या टियर-3 शहरों में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसे केवल सार्वजनिक बीमा कंपनियां ही सेवाएं दे सकती हैं।

अनुज गुलाटी: अर्थव्यवस्था के साथ बीमा क्षेत्र भी बढ़ा है। इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई है। सार्वजनिक बीमा कंपनियों के पास मौजूद ज्ञान उन्हें अलग मुकाम देता है और निजी क्षेत्र की कंपनियां उनसे सीख रही हैं। हालांकि खुदरा बाजार बढ़ने के साथ तकनीक आने से उनकी क्षमता में भी बदलाव आया है। निजी बीमा कंपनियों की तुलना में उनकी डिलीवरी की प्रक्रिया धीमी रही है।

नीलेश गर्ग: निजी क्षेत्र ने बाजार में नई मांग पैदा कर और संतुष्ट ग्राहकों के दम पर बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक बीमा कंपनियों की जगह कम हुई है। तीन तरह के ग्राहक हैं- कॉर्पोरेट ग्राहक, शहरी खुदरा ग्राहक और ग्रामीण खुदरा ग्राहक। पहले और तीसरे तरह के ग्राहकों के मामले में सार्वजनिक बीमा कंपनियां अपनी क्षमता, ज्ञान और ग्रामीण पहुंच के चलते बेहद मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन नई सदी के डिजिटल ग्राहकों के मामले में निजी बीमा कंपनियों को अपनी तेजी एवं तकनीक के चलते बढ़त मिली हुई है।

बाएं से दाएं: एक्को जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ वरुण दुआ, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ अनुज गुलाटी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडी और प्रबंध निदेशक भार्गव दास गुप्ता, बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक तमाल बंधोपाध्याय, जीआईसी सीएमडी एलिस वैद्यन, टाटा एआईजी के एमडी और सीईओ नीलेश गर्ग

भार्गव दासगुप्ता: सार्वजनिक बीमा कंपनियों का कुछ समय तक ध्यान बाजार हिस्सेदारी पर ही था लेकिन अंडरराइटिंग की कीमत पर बाजार हिस्सेदारी से हमेशा ही नुकसान होता है। अब हम उस मोर्चे पर सुधार देख रहे हैं। सभी सरकारी बीमा कंपनियां कीमत निर्धारण एवं अंडरराइटिंग में सुधार कर रही हैं। उनके पास अधिक भविष्योन्मुख पहलुओं में निवेश के लिए पूंजी होगी।

घाटे की अंडरराइटिंग

वैद्यन: बीमा कंपनियों का तिमाही आधार पर आकलन नहीं किया जा सकता है। दुनिया भर में बीमा कंपनियों का सालाना प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है। सामान्य बीमा बाजार वर्ष 2007 में प्रॉपर्टी एवं आगजनी को शुल्क-मुक्त किए जाने के बाद से ही अंडरराइटिंग घाटा उठा रहा है। इसने सभी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन निवेश आय का परिवेश काफी अच्छा है और यह अंडरराइटिंग से हो रहे नुकसान को कम कर रहा है।

दासगुप्ता: भारत के लेखा मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी हैं। भारत की सामान्य बीमा कंपनियों का साझा अनुपात उतना बुरा नहीं है जितना नजर आता है। बीमा, खासकर सामान्य बीमा का कारोबार अस्थिर है। कुछ तिमाहियों में हम निवेश पर नुकसान उठा रहे होंगे क्योंकि हम निवेश को दीर्घावधि नजरिये से देखते हैं। मैं निवेशकों से बीमा उद्योग को तिमाही के बजाय दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य से देखने का अनुरोध करूंगा।

वैद्यन: हम 13-15 फीसदी वृद्धि देख रहे हैं और यह दर बनी रहने वाली है। केवल समय की बात है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता बीमा बाजार बन जाए। अभी हम जीवन बीमा में 10वां बड़ा बाजार हैं और सामान्य बीमा में हम दुनिया में 15वें स्थान पर हैं। वक्त बीतने के साथ यह लाभप्रद भी हो जाएगा।

पुरुष एकाधिकार को तोड़कर शिखर पर पहुंच रही महिलाएं

अमृता पिल्लई और रोमिता मजूमदार

शेयर कारोबार, कोडिंग और प्रशासनिक पदों पर कुछ समय पहले तक केवल पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं ने शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि यह स्वागतयोग्य बदलाव है लेकिन अधिकांश महिलाओं का मानना है कि अभी मानसिकता में बदलाव की काफी आवश्यकता है।

पुरुष प्रधान इन तीनों क्षेत्रों में से शेयर बाजार में महिलाओं ने बड़ी भूमिकाएं हासिल कर ली हैं। आईसीआईसीआई सिक्वेरिटीज की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यधिकारी शिल्पा कुमार बताती हैं कि ब्रोकरेज फर्मों के स्वामित्व मॉडल में बदलाव ने इस मानसिकता को तोड़ा है।

वह कहती हैं, 'एक कारण यह है कि अधिकांश ब्रोकरेज परिवार द्वारा संचालित की जाती हैं और सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से घर का पुरुष ही इसे चलाता था। इसे बदलने में कई वर्ष का समय लग गया और अब पेशेवर तौर पर प्रबंधित ब्रोकरेज फर्म केंद्रीय भूमिका में हैं।'

पिछले कुछ सालों में वित्तीय सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी बढ़ोतरी हुई है। मोडलिस ऐंड कंपनी भारत की मुख्य कार्यधिकारी मनीषा गिरोत्रा बताती हैं कि पहले मानते थे कि महिला बैंकर केवल रिटेल बैंकिंग तक ही सीमित होती हैं। वह कहती हैं, 'ट्रेजरी, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पुरुषों का ही वर्चस्व देखा जाता



था। आज आप वित्तीय सेवाओं के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी देख सकते हैं।'

कंप्यूटर कोडिंग एक नया क्षेत्र है जहां महिलाएं अपना स्थान बना रही हैं। महिला हैकाथन के पिछले 3 साल के आंकड़े उत्पादजनक रख दिखा रहे हैं। वर्ष 2016 के हैकाथन में 149 महिलाओं ने हिस्सा लिया था और यह आंकड़ा बढ़कर 2017 में 255 तथा 2018 में 425 पर पहुंच गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2019 में पुरुष-महिला भागीदारी अनुपात 60:40 था और इसमें 3,000 से भी अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे क्षेत्रों में भी महिला प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि प्रतिनिधित्व में महिलाओं का प्रतिशत अधिक प्रभावशाली नहीं है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सालाना रिपोर्ट से मिले आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016-17 में 229 महिला प्रतिभागियों का चयन हुआ जबकि 2006 में 105 महिलाओं का ही चयन हुआ था। हालांकि आंकड़े बढ़ने के बाद भी प्रतिशत

प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर रहे जोर

में गिरावट दर्ज हुई है। साल 2016-17 में चयनित महिला अभ्यर्थियों का प्रतिशत 19.67 था जबकि 2006 में 21.3 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया गया था।

हालांकि कुछ महिला आईएएस अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति की प्रकृति काफी चुनौतीपूर्ण है। 1995 बैच की आईएएस अधिकारी अश्विनी भिडे कहती हैं, 'मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ऐसी बातें सुनी हैं कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए काफी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हालांकि राज्य सरकार ने 1993 की नीति के तहत राज्य सेवा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दीं। इससे शुरुआती स्तर पर कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे जैसे हम ऊपरी पदों पर जाते हैं तो समस्या बढ़ने लगती है।'

इस सबके बावजूद, महिलाओं को शीर्ष पदों पर पहुंचने या मानसिकता में बदलाव का इंतजार है तो कुछ अभी भी परिवार की जिम्मेदारियों से लड़ाई लड़ रही हैं।

‘निवेशकों के पैसे की बचत हो प्राथमिकता’

पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य बीमा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश लोग इलाज का महंगा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। पिछले पांच साल से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रीमियम 25 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा बीमा कंपनियां कंपनियों की ग्रेच्युटी को भी प्रबंधन कर रही हैं और यही वजह है कि बीमा क्षेत्र

में भारी निवेश हो रहा है। यह पैसा देश में बुनियादी क्षेत्र में लग रहा है। साठे ने कहा, 'देश के आर्थिक विकास में बीमा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसमें बुनियादी क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन प्रावधान हैं जिससे देश की जोखिम लेने की क्षमता मजबूत होती है।' उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र को अपने उत्पादों को सरल बनाने पर जोर देना चाहिए और धोखाधड़ी से बेहतर ढंग से निपटना चाहिए।

साठे ने कहा कि नोटबंदी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), इंडियास्टैंक और सरकार की नई योजनाओं से बीमा क्षेत्र को बल मिला है। साथ ही नई पीढ़ी के उपभोक्ता बीमा उत्पाद खरीद रहे हैं और वे प्रौद्योगिकी से अच्छी तरफ वाकिफ हैं। बीमा क्षेत्र अपनी पहुंच और कारोबार बढ़ाने के लिए ऑटोमैशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां म्युचुअल फंड का करीब 40 फीसदी कारोबार

केवल एक शहर मुंबई से आता है वहीं बीमा की ग्रामीण बाजारों में व्यापक पहुंच है। साठे ने कहा, 'हमने 25 करोड़ लोगों को 33 करोड़ पॉलिसी बेची हैं और इसमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है। जहां तक पहुंच का सवाल है तो मुंबई में जीवन बीमा केवल 11 फीसदी लोगों के पास है वहीं म्युचुअल फंड 39 फीसदी लोगों के पास है।' उन्होंने कहा, 'हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि बीमा बेहतर है या म्युचुअल फंड। सबकुछ अच्छा है। गैर वित्तीय बचत ठीक नहीं है। जिस माध्यम से भी लोगों के पैसे की बचत होती है वह अच्छा है।'